Papes (2)

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17-M-**GS2**

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): विकास गुप्ता

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 2 / 3rd Oct-2017.

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	0	1	3	3	3	4

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Vikas

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

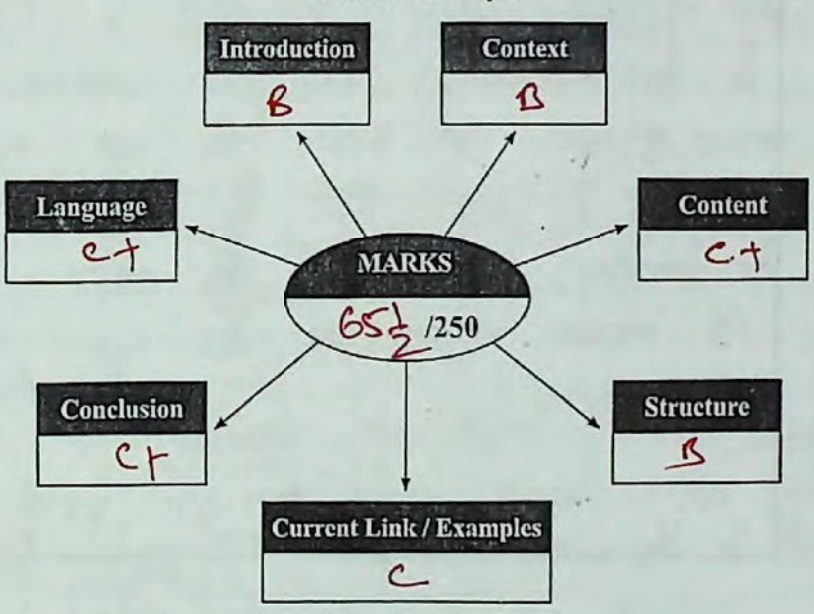

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

दृष्टि
The Vision

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

उत्तर में प्रभावोत्पादक संदर्भ तथा उदाहरणों का समावेशन करें।

विश्लेषण क्षमता में सुधार की गुंजाइश है।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज़' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

उत्तर लोकतंत्र में 'शक्तियों के पृथक्करण' एवं 'नियंत्रण एवं संतुलन' जैसे सिद्धांत शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को संतुलित रखते हैं, वैसे ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया इन तीनों अंगों पर जनता के दबाव द्वारा लोकतंत्र को संतुलित रखता है। परंतु, पिछले दो दशक में आपसी प्रतिस्पर्द्धा एवं व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने के कारण इस चौथे स्तंभ की जवाबदेही जनता एवं लोकतंत्र के प्रति कम हुई है। वर्तमान में मीडिया में व्याप्त कई समस्याओं में 'पेड न्यूज़' भी एक प्रमुख समस्या है।

'पेड न्यूज़' का तात्पर्य है किसी राजनीतिक दल या चुनाव प्रत्याशी द्वारा अपने चुनाव में अप्रत्याशित लाभ लेने के लिए मीडिया में धन प्रदान कर समाचार

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

प्रकाशित करवाना। इस प्रकार 'पेड न्यूज' वह समाचार है जो धन या अन्य प्रकार के लाभों के एवज में मीडिया द्वारा जारी किया जाता है।

'पेड-न्यूज' के कई दुष्परिणाम होते हैं। जैसे
(1) मतदाता को गुमराह किया जाता है। यह मतदाता के सही सूचना प्राप्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

पेड न्यूज का भारतीय लोकतंत्र के ऊपर प्रभाव

(2) स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया कुप्रभावित होती है।
(3) मीडिया के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ती है।
(4) मीडिया द्वारा व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता स्वस्थ लोकतंत्र हेतु उचित नहीं।
(5) निर्वाचन आयोग की 'खर्च-सीमा' के नियमों का उल्लंघन होता है।

उपरोक्त दुष्परिणामों के चलते 'पेड-न्यूज' की समस्या से निजात पाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं_

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(1) जन-प्रतिनिधित्व कानून 1951 में 'पेड-न्यूज़' को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। वर्तमान में निर्वाचन आयोग को 'खर्च-सीमा' के उल्लंघन के आधार पर कार्यवाही करने का तो अधिकार प्राप्त है; परंतु, 'पेड-न्यूज़' का नहीं।

अन्य उपाय उल्लेख करें

(2) जन-प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन द्वारा चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान मीडिया के संबंध में भी आचार-संहिता ~~निर्मित~~ करने का अधिकार दिया जा सकता है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पूर्वशर्त है। लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु मीडिया की जवाबदेही आवश्यक है। अतः मीडिया को व्यावसायिक हितों की जगह जनता के प्रति उत्तरदायित्वों को प्राथमिकता ~~दी जानी~~ देनी चाहिए।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	1.5	1.5	0.25	—	0.25	
Grade	A	C	C	C		B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राज़ील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

उत्तर)

'ब्राज़ील घोषणापत्र' (Brasil Declaration) सड़क सुरक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण वैश्विक घोषणापत्र है जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के सड़क सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने एवं सड़क परिवहनकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रों की जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।

[Evaluator's remark: ब्रासिलीया घोषणापत्र प्रमुख विशेषताएं लिखें]

भारत द्वारा 'ब्राज़ील घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परंतु, फिर भी लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में हाल ही में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तावित किया गया है जिसके प्रमुख प्रावधान हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(2) सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान।

(3) दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने वाले ~~व्यक्ति~~ (Good Samaritan) को [illegible] प्रोत्साहित करना।

[illegible] दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय करना जैसे लाइटिंग, गड्ढों को ठीक करना आदि।

एक सुरक्षित परिवहन देश के नागरिकों के जीवन के साथ-साथ देश की आर्थिक समृद्धि हेतु भी आवश्यक है।

2.5

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उत्तर रचनात्मक स्वतंत्रता एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। परंतु, हाल ही में 'केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (CBFC) द्वारा लिए गए फिल्म संबंधी कुछ निर्णयों की स्वामित्व एवं मूलाधिकारों के ~~आधार पर~~ उल्लंघन के आधार पर आलोचना की गई। गौरतलब है कि भारत में फिल्मों के विनियमन संबंधी दायित्व 'केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' को सौंपा गया है।

CBFC की पृष्ठभूमि लिखें
स्थापना

'केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' द्वारा फिल्मों के दृश्यों के संबंध में आपत्ति व्यक्त करना फिल्म-निर्माता के हितों को कई आधारों पर प्रभावित करता है। जैसे -

(1) यह निर्माता की रचनात्मक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

(2) निर्माता के 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के मूलाधिकार का उल्लंघन है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(3) क्या उचित है और क्या अनुचित ? यह निर्णय आत्मनिष्ठ है वस्तुनिष्ठ नहीं। यह प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों के रुझान पर निर्भर करता है।

(4) निर्माता का अपनी फिल्म पर अधिकार है। अतः प्रमाणन हेतु किसी बोर्ड की स्वीकृति कहीं न कहीं स्वामित्व (कॉपीराइट) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

कुछ उदाहरण दें

परंतु, निर्माता का अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि फिल्मों का सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक होता है। अतः प्रमाणन की आवश्यकता कई आधारों पर बनी हुई है। जैसे-

(1) फिल्मों का बहुआयामी एवं समाज पर व्यापक प्रभाव होना।

(2) भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विविध वर्गों के हितों की रक्षा, उनके विश्वास, सम्मान की सुरक्षा।

(3) स्वस्थ जनमत के विकास हेतु सरकार की भूमिका।

Copyright – Drishti The Vision Found
Scanned by CamScanner

(कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
Please do not write anything except the question number in this space)

अतः भारतीय सिनेमा की समग्रता एवं भारत की विशिष्ट संस्कृति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपाय सोचे जा सकते हैं

(1) 'श्याम बेनेगल समिति' की अनुशंसाओं को स्वीकार किया जा सकता है।

(2) बोर्ड का कार्य प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) तक सीमित रहे, सेंसरशिप पर नहीं।

(3) फिल्म के मूल्यांकन का अधिकार दर्शक वर्ग पर छोड़ा जा सकता है।

भारतीय सिनेमा की बहुआयामी प्रकृति इस संदर्भ में एक सकारात्मक संकेत है। अर्थात - सभी प्रकार की एवं सभी प्रकार के सामाजिक वर्गों, हितों, रुझानों की फिल्में भारत में बनती रही हैं। अतः ~~भारतीय जनता को~~ फिल्मों का प्रमाणन किया जाना ही उचित प्रतीत

3.5

फिल्म सेंसरशिप और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन की आवश्यकता दर्शाएं।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की माँग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

उत्तर

भारतीय राजव्यवस्था में 'संविधान की सर्वोच्चता' स्वीकार करते हुए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। ~~भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 105 संसद को कई शक्तियां~~ संविधान में विधि निर्माण से लेकर विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार संसद को प्रदान किए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद-368 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार भी प्राप्त है।

संसद को प्राप्त उन्मुक्तियों तथा शक्तियों की चर्चा करें

चूँकि भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के बीच संविधान एक संतुलन की स्थापना करता है। फिर भी संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण शक्ति संसद के पास है। अतः संसद का कामकाज सही एवं सुगम रूप से चलने की आवश्यकता है। इसके लिए हाल ही में कुछ विद्वानों द्वारा 'एक निगरानी आयोग' का सुझाव दिया

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

गया है। इस प्रकार संसदीय निगरानी आयोग के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:-

(1) इससे संसद सदस्यों पर कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने हेतु स्वस्थ दबाव निर्मित होगा।

(2) संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता पर आयोग की रिपोर्ट द्वारा जनमत का दबाव भी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बनेगा।

(3) राजनीतिक हितों के लिए संसदीय कार्यवाही को बार-बार बाधित करने का आचरण कम हो सकेगा।

(4) संविधान में अवांछित परिवर्तन एवं लगातार अध्यादेशों का प्रयोग भी हतोत्साहित होने की संभावना बनेगी।

परंतु, यह इस विचार का एक पक्ष है। कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जिनसे इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता महसूस नहीं होती:-

(1) संसदीय कार्यवाही की सफलता अर्थात् उसकी उत्पादकता की रिपोर्ट अभी भी

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

जनता के समक्ष आती ही है।

(2) संसदीय विधियों के 'न्यायिक पुनरीक्षण' का अधिकार न्यायपालिका के पास है।

(3) संविधान में अवांछित परिवर्तनों का मामला 'संविधान के मूल ढाँचे' की धारणा से संतुलित होता है।

(4) जनप्रतिनिधियों के आचरण हेतु विशेषज्ञों [illegible] का गठन लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करता है।

इस प्रकार, वर्तमान समय में संसदीय कार्यवाही सुगम एवं सुचारु रूप से चले एवं संविधान में समयानुकूल वांछित परिवर्तन हों, इसके लिए वर्तमान उपस्थित ढाँचों एवं प्रक्रियाओं को ही कुशल बनाना पर्याप्त होगा। इस हेतु मीडिया को अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करना उपयोगी होगा।

4.5

स्वेच्छाचारिता पर लगाम है
पहले से ही उपलब्ध स्वतंत्रता
की चर्चा

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Fo
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उत्तर

भारतीय राजव्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भारत को अनुच्छेद -1 के तहत 'राज्यों' का संघ (Union of States) घोषित किया गया है। संविधान में कई राज्यों एवं क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे -

(1) A-370 द्वारा जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान

(2) A-371 के विभिन्न खंडों द्वारा मणिपुर, नागालैण्ड, गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम आदि के संबंध में प्रावधान।

(3) A-244 द्वारा पाँचवी एवं छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान।

(4) इसके अलावा पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के आधार पर 11 राज्यों को (प्रायः पूर्वोत्तर एवं हिमालयी) को 'विशेष राज्य का दर्जा'।

राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने के उद्देश्यों को लिखें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

हाल ही में, इस प्रकार के विशेष दर्जों के चलते कई आंदोलन सामने आए। जैसे- नागालैण्ड में महिला आरक्षण के संबंध में A-371 द्वारा प्राप्त सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के संबंध में।

(2) गोरखालैण्ड की मांग के संबंध में कि उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाया जाए या छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।

(3) जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35(A) की समाप्ति के संबंध में देशभर में विरोध प्रदर्शन।

(4) हाल ही में तेलंगाना एवं इसकी तरह कई राज्यों द्वारा 'विशेष राज्य का दर्जा' प्राप्ति के संबंध में।

उपरोक्त आंदोलनों को देखते हुए प्रतीत होता है कि राज्यों को प्राप्त विशिष्टता आंदोलनों का कारण बनती है। परंतु, वास्तविकता यह है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सहयोगी संघवाद एवं भारतीय अखंडता

आंदोलनों का राष्ट्रीय अखंडता तथा आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव स्पष्ट करें। एकता एवं अखंडता के प्रति

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि राज्यों की स्थिति के आधार पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान किए जाएँ। जैसे -

(1) पिछड़े राज्यों के लिए (विशेषत: पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों के लिए।

(2) आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति, प्रथाओं की सुरक्षा हेतु।

(3) जम्मू - कश्मीर जैसे भू - राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्य हेतु।

इस प्रकार विशिष्ट दर्जे की उपस्थिति भारतीय अखंडता को मजबूती प्रदान करने में सहायक रही है न कि आंदोलनों द्वारा इसे कमजोर करने में।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

उत्तर

'न्याय मिलने में देरी' अन्याय है। परंतु, भारतीय न्यायपालिका की वास्तविकता यह है कि इसमें वर्तमान समय में 3.2 करोड़ मामले विलंबित हैं। अतः विद्वानों द्वारा कई उपायों के तहत 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' का गठन भी एक उपाय के रूप में सुझाया गया है। इससे निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-

(1) AIJS द्वारा लगातार न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति।

(2) न्यायाधीश - जनसंख्या अनुपात में सुधार होगा।

(3) अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक पदों में कुशलता बढ़ेगी। इससे उच्चतर न्यायपालिका में अपीलीय मामलों की संख्या में कमी होगी।

(4) फास्ट ट्रैक न्यायालयों हेतु भी न्यायाधीशों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

अन्य लाभ का उल्लेख करें।

Copyright – Drishti The Vision

Scanned by CamScanner

इस प्रकार त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय न्यायपालिका में गुणात्मक सुधार समय की मांग है। अतः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यही कारण है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा कई मामलों में एवं हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भी इसके तीव्र गठन की आवश्यकता स्पष्ट की गई है।

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

उत्तर) भारत में प्रशासनिक अधिकरणों का गठन अनुच्छेद 323 (क) के आधार पर किया जाता है जिसे 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तें आदि से जुड़े मामलों को देखते हैं। लगातार बढ़ते मामले न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

निम्नलिखित आधार पर उत्पन्न करते हैं -

(1) प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर न्यायपालिका में लंबित अपीलीय मामले।

(2) अधिकरणों में प्रशासनिक विशेषज्ञों की उपस्थिति; जबकि न्यायपालिका विधि विशेषज्ञों की आवश्यकता पर आधारित है।

(3) इसके विभिन्न मामलों में न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार सीमित होता है।

इस प्रकार, प्रशासनिक अधिकरणों में वृद्धि कहीं न कहीं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को सीमित करती हुई प्रतीत होती है। परंतु, प्रशासन से जुड़ी विभिन्न स्थितियों की जानकारी प्रशासनिक विशेषज्ञों को बेहतर होती है। अतः एक सीमा तक इन अधिकरणों का गठन एवं इनका कुशल संचालन न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ को कम ही करता है।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उत्तर) लोकतंत्र की सफलता हेतु स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। हाल ही में बजट 2016-17 में सरकार द्वारा चुनावी वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं। जैसे -

(1) राजनीतिक दलों को नकद द्वारा प्राप्त अनुदान की सीमा 2000 ₹ निर्धारित करना।

(2) 2000 ₹ से अधिक अनुदान हेतु चेक एवं डिजिटल भुगतान की अनिवार्यता।

(3) आयकर संबंधी लाभों की प्राप्ति हेतु तय समय पर ~~[illegible]~~ रिटर्न फाइल करना।

(4) ~~[illegible]~~ 'चुनावी बॉंड' (electoral bond) की धारणा की प्रस्तावना जिसके तहत बॉंड की खरीद द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को अनुदान उपलब्ध करवाना।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

उपरोक्त कदम स्वागत योग्य हैं क्योंकि -

(1) चुनावों एवं राजनीतिक दलों के अनुदान में काले धन का प्रयोग हतोत्साहित होगा।

(2) 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' सर्वे में यह जानकारी कि 2/3 अनुदान अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुए हैं।

(3) राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग में कुछ सीमा तक पारदर्शिता आने की संभावना।

(4) 'चुनावी बॉन्ड' की धारणा द्वारा राज्य वित्तपोषित चुनावों की ओर एक सकारात्मक पहल।

परंतु, बजट में प्रस्तावित उपाय राजनीतिक दलों की फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाने में कुछ सीमाओं से भी युक्त हैं। जैसे -

(1) 2000 ₹ से कम अनुदान के संबंध में अज्ञात स्रोत की उपस्थिति।

Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(2) तय समय पर रिटर्न फाइल न करने पर दंडिक प्रावधानों की अनुपस्थिति।
(3) राजनीतिक दलों का RTI के अधीन न होना।

उपरोक्त सीमाओं को दूर करने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सोचे जा सकते हैं। जैसे -
(1) बेनामी 2000 रु की सीमा हटाई जा सकती है। पूर्णतः चेक, डिजिटल भुगतान एवं सभी स्रोतों का उल्लेख।
(2) स्वतंत्र संस्था द्वारा ऑडिटिंग की प्रक्रिया।
(3) RTI के अधीन लाया जा सकता है।

इस प्रकार राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता समय की मांग है।

अन्य सुधारों की चर्चा करें

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? 12.5
(250 शब्द)

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. 12.5
(250 words)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उत्तर) ~~अ~~ अवैध आय की समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक कारण अचल संपत्ति क्षेत्र का दुरुपयोग भी रहा है। हाल ही में, भ्रष्टाचार को रोकने एवं उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा हेतु अचल ~~संपत्ति~~ संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया है जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :-

(1) अचल संपत्ति विकास प्राधिकरण के गठन द्वारा अचल संपत्ति डेवलपर हेतु पंजीकरण की अनिवार्यता।

(2) डेवलपर द्वारा उपभोक्ताओं से ली गई 70% राशि संबंधित परियोजना फंड में ~~आवंटित~~ आवंटित करना।

RERA [illegible] मुख्य [illegible] बताएं
[illegible] भूमिका

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

(3) तय समय सीमा के अन्दर उपभोक्ताओं को उनकी संपत्ति उपलब्ध कराना।

(4) प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान।

इस प्रकार रियल एस्टेट क्षेत्र लंबे समय से काले धन के दुरुपयोग का प्रमुख क्षेत्र रहा है। बेनामी संपत्ति विधेयक, विमुद्रीकरण एवं RERA (रियल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम) काले धन को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं।

परन्तु, उपरोक्त अधिनियम के समक्ष चुनौतियां भी हैं, जैसे:-

(1) रियल एस्टेट क्षेत्र को 'विकास का इंजन' माना जाता है। कई विनियमन के कारण यह क्षेत्र मन्दी आर्थिक संवृद्धि को धीमा कर सकती है।

RERA के सकारात्मक पहलू के लेकर ...

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

(2) प्रणाली क्रियान्वयन की चुनौती।

एक प्रकार उचित क्रियान्वयन द्वारा उपरोक्त संपत्ति विकास विनियमन अधिनियम को प्रभावी बनाया जा सकता है।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Found

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उत्तर) संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को 'पूर्ण न्याय का अधिकार' प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा किसी मामले में कोई ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है जिसके द्वारा न्यायालय की नज़र में पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

'पूर्ण न्याय का अधिकार' न्यायालय को किसी भी मामले में प्रभावी हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता है। कई मामलों में शीर्ष न्यायालय द्वारा इस अधिकार का प्रभावी उपयोग किया गया है। जैसे -

(1) भूतिनत कार्बाइड मामले में जिसमें अलग-अलग अदालतों में दाखिल मामलों को निपटाने में लंबा समय लगता, शीर्ष न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि की घोषणा किया जाता।

(2) सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालयों को बंद करने के समय शीर्ष न्या

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया जाता कि सरकार अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के पदों का सृजन करें ताकि जनता का न्याय का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

(3) हाल ही में, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति।

यह सही है कि अधिकांश मामलों में शीर्ष न्यायालय द्वारा संविधान एवं जन हितों के आधार पर ही इस अधिकार का उपयोग हुआ है। परंतु, इस अधिकार के उपयोग की कुछ सीमायें भी हैं :-

(1) न्यायपालिका को असीमित अधिकार प्रदान करना विधाई शक्तियों के पृथक्करण एवं संतुलन की उपेक्षा होती है।

(2) न्यायिक अतिक्रमण जहाँ कार्यपालिका

अनुच्छेद 142 के साथ अनुच्छेद 141 का उल्लेख करें। संपूर्ण न्याय में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

एवं विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप।

(3) नियम-निर्माण एवं निर्देशों का निर्माण विधायिका का कार्य है। न्यायपालिका का कार्य उनका मूल्यांकन है।

इस प्रकार अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को एक प्रभावशाली अधिकार प्रदान करता है। परंतु, न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिक्रमण के बीच अंतर केवल एक महीन रेखा का है। अतः इसका संतुलित उपयोग ही उचित है।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

उत्तर)

सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं को प्रदान करने हेतु 'आधार का चयन' उसकी अनिवार्यता एवं ~~[illegible]~~ निजता के अधिकार की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रश्नों में रहा है।

सरकार द्वारा कल्याणकारी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता कई दृष्टियों से लाभकारी होगी।

जैसे :-

(1) लक्षित वर्गों को कल्याणकारी उपायों का लाभ प्राप्त होगा।

(2) कल्याणकारी उपायों जैसे - सब्सिडी में लीकेज की समस्या का निदान।

(3) आधार के माध्यम से बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण लक्षित वर्ग की निश्चित समय, स्थान पर उपस्थिति से मुक्त करेगा।

(4) कल्याणकारी सेवा प्रदान करने वाले

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
दृष्टि The Vision
Copyright– Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

ढाँचे में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लाल-फीताशाही कम होगी।

(5) सरकारी कल्याणकारी उपायों की सफलता की संभावना में वृद्धि होगी।

परंतु, आधार की अनिवार्यता सभी सेवाओं के लिए करना कई अन्य मुद्दों को भी उत्पन्न करता है। जैसे -

(1) शीर्ष न्यायालय द्वारा लगातार आधार की अनिवार्यता का खंडन किया जाना।

(2) अभी भी एक बड़ा तबका बैंकिंग सेवाओं की पहुँच से बाहर है।

(3) डिजिटल साक्षरता का अभाव।

(4) विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्रित वर्गों के आधार डाटा की सुरक्षा एवं दुरुपयोग की आशंका।

इतना ही नहीं, कहीं न कहीं विभिन्न

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

सेवाओं हेतु आधार की अनिवार्यता लक्षित वर्गों में भ्रम की स्थिति भी पैदा करती है। एक भ्रम तो लगातार सरकार के अनिवार्यता के निर्देश एवं शीर्ष न्यायालय के वैकल्पिक होने के निर्देश के कारण बना रहता है। इसके अलावा अन्यत्र विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं हेतु आधार की अनिवार्यता लक्षित वर्गों में भ्रम एवं संदेह की उत्पत्ति करती है।

आधार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय

3.5

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

उत्तर) विश्व मुद्रा कोष (IMF) के वर्किंग पेपर में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को विकासशील देशों में निम्नतम देशों में से एक बताया गया है। वहीं, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकड़ों के तहत भी इसी ओर संकेत किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर होने के निम्नलिखित कारण संभावित हैं:

(1) महिलाओं के लिए विशेष क्षेत्रों की सीमितता जैसे - शिक्षा क्षेत्र, कॉल सेंटर क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि।

(2) सूचना - प्रौद्योगिकी के दौर में लगातार नए - नए क्षेत्रों में महिलाओं की पहुँच नहीं होना।

(3) महिला शिक्षा एवं कौशल विकास का अभाव जिसके कारण नए - नए क्षेत्रों में महिलाओं की पहुँच सीमित

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(4) मातृत्व संबंधी लाभ एवं अवकाश के चलते पुरुष श्रमबल को प्राथमिकता देना ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट के निम्नलिखित कारण संभावित हैं। जैसे -

(1) कृषि का पिछड़ापन, जोतों का आकार सीमित होना, कृषि लाभ में लगातार कमी।

(2) पितृसत्तात्मक ढांचा जिसके कारण महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कार्य करना उचित नहीं समझा जाता।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित अवसरों की उपस्थिति। अतः कृषि लाभ के कम होने के कारण इन अवसरों की ओर भी पुरुषों का आकर्षित होना। (जैसे - पशुपालन।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के उपरांत श्रम बल भागीदारी संबंधी आंकड़े महिला श्रम बल भागीदारी में गिरावट को सूचित

मॉडल उत्तर देखें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

करते हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर्याप्त नहीं है। इसमें गिरावट महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को विफल कर सकती है।

भारत में उपयोग सुधारें

2.5

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space except question number)

उत्तर)

'धर्मनिरपेक्षता' भारतीय संविधान में प्रस्तावना में घोषित उद्देश्यों में से एक है। भारतीय संदर्भ में इसका तात्पर्य पंथनिरपेक्षता से है जो कि पश्चिम की ~~धर्मनिरपेक्षता~~ 'सेक्युलर' धारणा से अलग है। प्राचीन काल ~~में~~ में ~~अशोक~~ अशोक, मध्यकाल में अकबर आदि शासकों द्वारा 'धर्मनिरपेक्षता' ~~को~~ को राज्य-नीति का अभिन्न अंग माना गया।

'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हाल ही में लगातार समाचारों में रहा है। 'धर्मनिरपेक्षता' के संबंध में वर्तमान परिदृश्य को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है:-

(1) विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य टकराव संबंधी खबरें।

(2) ~~[illegible]~~ धर्म विशेष संबंधी वैयक्तिक विधियों के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष

दृष्टि The Vision
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

वैकल्पिक विधियों की मांग - समान सिविल संहिता की मांग। (ट्रिपल तलाक मामला।)

(3) ~~अल्पसंख्यक~~ धर्म विशेष को तरजीह देने का आरोप। (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा एवं मोहर्रम संबंधी भेदभाव का आरोप।)

(4) राज्य द्वारा धार्मिक आधार पर शरणार्थियों को वरीयता का आरोप। (रोहिंग्या मामला, हिंदू शरणार्थियों को निवास, नागरिकता अधिकार)

धर्मनिरपेक्षता - द्रुमिलाई ... की नुमिलाई ... रोहिंग्या को ... करने में ... की चर्चा करें।

लगातार समाचारों में इन मामलों के आधार पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खतरे में होने की बात कही गई है। परंतु, भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। इसके संबंधित स्थापना एवं सकारात्मक कारण निम्नलिखित हैं। जैसे -

(1) प्रस्तावना में उल्लिखित होना।

(2) मूलाधिकारों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(3) धर्म, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।

(4) राज्य द्वारा सभी धर्मों के नागरिकों की उन्नति, विकास का प्रयास। जैसे - मुसलमानों के लिए 'उस्ताद योजना', छात्रवृत्ति योजना (मौलाना आज़ाद), पारसी जनता हेतु 'जियो पारसी' योजना, बौद्धों हेतु 'बुद्ध सर्किट निर्माण' आदि।

[illegible] सदन के विपरीत: सोशल मीडिया के माध्यम से ध्रुवीकरण की घटनाएं बढ़ी हैं। अत: आवश्यकता सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने की है।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान लिखें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 द्वारा सरकार भारतीय नागरिकों की खाद्य सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध दिखाई देती है परंतु, पिछले कुछ समय से खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक किसान वर्ग की असुरक्षा बढ़ती जा रही है जिसे लगातार होती आत्महत्याओं, जगह-जगह पर प्रदर्शनों के द्वारा देखा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे -

(1) कृषि की बिगड़ती स्थिति; लगातार दो वर्षों से सूखा, कृषि लागत में वृद्धि एवं लाभों में कमी, विभिन्न फसलों के उत्पादन में कमी।

(2) अधिकांश कृषकों द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को कृषक नहीं बनाने की इच्छा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScan

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(3) बढ़ती जनसंख्या एवं लगातार छोटे होते कृषि-जोत।

(4) कौशल एवं पर्याप्त भंडारण क्षमता की कमी।

अन्य वैज्ञानिक कारणों का उल्लेख करें।

(5) सरकार द्वारा MSP के माध्यम से कुछ फसलों की ही खरीद एवं उनके भंडारण की कुशल व्यवस्था का अभाव।

अतः खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं भारतीय कृषि एवं कृषकों की स्थिति में सुधार लाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे:-

(1) स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना जैसे:-
- (i) सीलिंग पार भूमि एवं खराब भूमि का वितरण।
- (ii) बीमा सुविधा प्रदान करना।
- (iii) MSP लागत का 150%।
- (iv) ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा आदि।

(2) कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुसार कृषकों को सलाह देना।

(3) कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करना

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

एवं APMC एक्ट में संशोधन करना।
(4) ऑनलाइन मार्केटिंग का लाभ प्राप्त करना।
(5) परिवहन, भंडारण की सुविधा।
(6) बीमा सुविधा आदि।

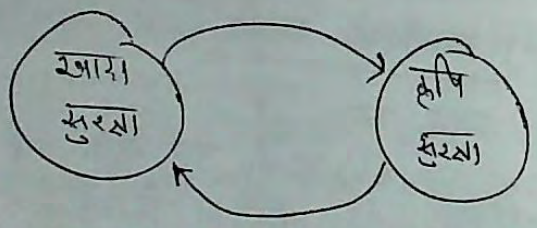

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं कृषि सुरक्षा दोनों नितांत आवश्यक है। इसके लिए सरकारी प्रयास जैसे – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, e-NAM, ऋणमाफी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि प्रयास प्रशंसनीय है।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

दृष्टि
The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

उत्तर)

जिस प्रकार कार्ल मार्क्स के समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों के आकर्षण के बाद ज्याँ पॉल सार्त्र के अस्तित्ववादी विचारों के तहत व्यक्ति को अधिक केंद्रित भूमिका मिली; उसी प्रकार भारतीय समाज भी संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अधिक आकर्षित होता जा रहा है। इस स्थानांतरण के कई संभावित कारण माने जा सकते हैं। जैसे -

(1) व्यक्तिवादी अधिकारों की बढ़ती आकांक्षा जिनकी पूर्ति एकल परिवारों में होने की संभावना अधिक।

(2) वैश्वीकरण के दौर में समाज पर लगातार पड़ता पश्चिमी समाज का प्रभाव।

(3) धार्मिक, नैतिक मूल्यों में गिरावट के चलते सामाजिक दबाव शिथिल हुए हैं। इससे व्यक्तिवादी आकांक्षाओं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
दृष्टि The Vision
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की पूर्ति की इच्छा बढ़ी है।

(4) एकल परिवारों में निजता के अधिकार की सुरक्षा की अधिक संभावना।

(5) महानगरों में जीवनशैली, सीमित आवासीय उपलब्धता आदि कारणों के कारण भी एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है।

अन्य कारणों का उल्लेख करें

परंतु, पिछले कुछ समय में जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की दृष्टि से तो यह चलन ठीक है, वहीं, अवसाद, फिजूलखर्च, मानसिक तनाव भी व्यक्तिगत एकल परिवारों में अधिक देखा गया है। इसके कारण कई समस्याएँ भी सामने आई हैं जैसे -

(1) अवसाद, मानसिक तनाव व अकेलेपन में वृद्धि।

(2) संबंधों में टूटन, उपभोक्तावादी विचारधारा।

(3) बच्चों का पालन-पोषण ठीक से नहीं हो पाना एवं सामाजिक प्रतिरोधकता की कमी।

Scanned by CamScanner

इस प्रकार लगातार व्यक्तिवादी आकांक्षाओं के चलते एवं महानगरीय अभिलाषावादी सामाजिक दबावों के कारण भी एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है जिसके कुछ लाभ एवं सीमाएँ (हानियाँ) हैं।

पारिवारिक मूल्यों की आवश्यकता को निष्कर्ष में [illegible] दें।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें (Please do not write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Scanned by CamScanner

15. हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Our education system has failed to integrate the rural into the larger political community. Comment. (250 words) 12.5

(कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें) (Please do not write anything except the question number in this space)

(कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें) (Please don't write anything in this space)

उत्तर) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही ग्रामीण आबादी का अधिक होना लोकतंत्र में ग्रामीणों के पक्ष में एक अच्छी स्थिति थी परंतु, इतने वर्षों के बाद भी ग्रामीण आबादी एक प्रभावशाली दबाव समूह (pressure group) बनने में असफल रही है। इसका एक कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली भी है :-

(1) भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत गुणवत्तायुक्त शिक्षा केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रही।

(2) ग्रामीण आबादी मात्र शिक्षा प्रणाली से वंचित रही। इसके कारण अपने अधिकारों के संबंध में ग्रामीण आबादी में जागरूकता का अभाव रहा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this

(3) गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अभाव के कारण ~~धनबल - बाहुबल~~ पर होने वाले चुनावों में ग्रामीण ~~जन~~ वोट बैंक की ~~राजनीति~~ का शिकार होना पड़ा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बौद्धिक कार्यों की ~~अपेक्षा~~ अन्य कार्यों से ... जुड़े।

(4) शहरी शिक्षित वर्गों द्वारा भी ग्रामीण लोगों के प्रति हेयदृष्टि की उपस्थिति रही। इसके कारण इस हेतु की समाप्ति के प्रति उत्तरदायित्व शिक्षित वर्ग द्वारा भी महसूस नहीं किया गया।

(5) यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों के संबंधित राजनीतिक नेता या तो धनबल या बाहुबल के आधार पर राजनीति में सक्रिय करते रहे और सक्रिय के बाद शहरी बनकर रह गए।

(6) गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रणाली की उपस्थिति के अभाव में जातीय बंधन, संकीर्णता आदि की उपस्थिति

Scanned by CamScanner

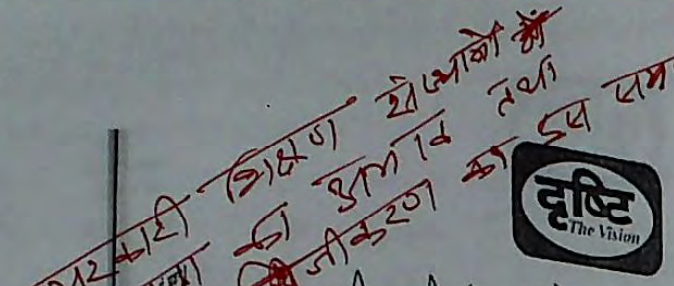

सरकारी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता का प्रभाव तथा शिक्षा के निजीकरण का इस समस्या में योगदान लिखें

बनी रही। ऐसे ग्रामीण समाज कभी विकासवादी मुद्दों पर एकीकृत नहीं हो पाता।

अतः समय की मांग है कि RTE के तहत मात्रात्मक के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीण आबादी एक राजनीतिक समुदाय के रूप में एकीकृत हो सके।

3.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words) 12.5

उत्तर) विमुद्रीकरण का तात्पर्य किसी विशेष मुद्रा के अमान्य घोषित कर ~~उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना~~ है। हाल ही में, भारत सरकार द्वारा 500 ₹ एवं 1000 ₹ के नोटों के संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई गई। विमुद्रीकरण के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लाभ विद्वानों द्वारा बताए गए। ऐसे ही एक लाभ कल्याणकारी कार्यक्रमों के संबंध में भी है। जैसे:-

(1) विमुद्रीकरण से प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इससे भविष्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन बेहतर होगा।

(2) सरकार को नकदी विहीन अर्थव्यवस्था के प्रसार का लाभ मिलेगा इससे लीकेज में कमी आएगी।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

(3) नकदी विहीन हस्तांतरण (DBT) द्वारा वंचित वर्गों को अधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि तकनीकी के लीकेज की समस्या लगातार कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलता का कारण रही है।

(4) विमुद्रीकरण से बैंकिंग वंचित वर्ग को बैंकिंग से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

कैशलेस अर्थव्यवस्था ... बेहतर ... तथा ... इत्यादि ... चर्चा करें)

परंतु, विमुद्रीकरण के उपरोक्त लाभ दीर्घकालिक हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा जिस वंचित वर्ग को लाभ पहुँचाया जाता है प्रायः वह वर्ग नकदी का ही उपयोग करता है। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ग को विमुद्रीकरण के कारण अल्पकाल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को भी कम किए जाने की आवश्यकता है।

(3)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उत्तर) हाल ही में, किसानों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं एवं ~~[illegible]~~ प्रदर्शनों के चलते कृषि संकट की ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ एवं उत्तर-प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषकों के ऋण को माफ़ किया गया। यह एक अस्थाई ~~[illegible]~~ है एवं अपर्याप्त राहत है।

क्योंकि :-

(1) अधिकांश कृषक असंस्थागत एवं अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं।

(2) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के तहत लगभग 70% ~~[illegible]~~ आत्महत्या करने वाले कृषक छोटे कृषक थे। (2015) छोटे कृषक सामान्यतः अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर ही निर्भर।

(3) बढ़ती कृषि लागत परंतु घटता कृषि लाभ। उत्पादन कम होने पर सूखा

Copyright : Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

A3

एवं उत्पादन अधिक होने पर कीमतों में तीव्र गिरावट।

(4) लगातार बदलती जलवायु दशायें अतः बढ़ती कृषि की सुभेद्यता एवं सीमित सिंचाई स्रोत।

(5) MSP के तहत भी देरी से भुगतान।
अतः कृषकों की स्थिति में सुधार हेतु अन्य उपायों की भी आवश्यकता है। जैसे -

(1) स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना जैसे -
(i) भूसुधार ; सीलिंग पार भूमि व खराब भूमि का वितरण।
(ii) सिंचाई सुविधा।
(iii) बीमा सुविधा आदि।

(2) (MSP) में लगातार वृद्धि एवं विविधीकरण ??

(3) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। इसके लिए PMKSY एवं नदी जोड़ो परियोजना एक उचित कदम।

सुधारों की जरूरत हेतु कृषि विस्तार सेवाओं, पशुपालन, Aquaculture इत्यादि पर चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(4) पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता।

(5) PMFBY के तहत बीमा कवरेज को व्यापक बनाना।

(6) एकीकृत कृषि बाजार के लाभ सुनिश्चित किए जाएँ। इस संदर्भ में सरकार की e-NAM पहल एक प्रशंसनीय कदम है।

(7) 'कृषि' विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना।

इस प्रकार कृषकों की दशा में सुधार हेतु व्यापक स्तरों पर बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है इनमें ऋणमाफी एक विकल्प हो सकता है परंतु एकमात्र विकल्प नहीं।

उपायों की व्यापक चर्चा करें

3.5

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

दृष्टि The Vision

19. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये। (250 शब्द) 12.5

The Consumer Protection Bill, 2015 will replace the Consumer Protection Act, 1986, compare and contrast both. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान किए गए। ~~लिए~~ जैसे:

(1) उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता का प्रचार प्रसार। (जागो ग्राहक जागो पहल)

(2) उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था :-

(i) जिला उपभोक्ता फोरम

(ii) राज्य उपभोक्ता आयोग

(iii) राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग।

हाल ही में, सरकार द्वारा लाए गए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
दृष्टि The Vision
Scanned by CamScanner

समय एवं उभरती नई चुनौतियों के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण संबंधी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ~~उत्पाद~~ विज्ञापन संबंधी है। इसके तहत विज्ञापनकर्ता की जवाबदेही निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए अभिनेताओं, क्रिकेटरों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन के संबंध में जवाबदेही तय की गई है जिससे उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों का सामना न करना पड़े।

इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 उपभोक्ता संरक्षण विधि, 1986 की सीमाओं को दूर करता है एवं उपभोक्ता-अधिकारों एवं उत्पादक कंपनियों द्वारा

उपभोक्ता 2015 विधेयक के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा

Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही आकर्षक जानकारियों से बचाता है। साथ ही, समाज पर व्यापक प्रभाव रखने वाले हस्तियों की उपभोक्ताओं के संबंध में जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।

इस विधेयक की आपूर्ति चर्चा करें

2.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

20. (a) लिंग गणनापत्र (Gender Scorecard) क्या है? कैसे यह भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये। 6

What is Gender Scorecard? How gender scorecard can become a beneficial tool for welfare of half population of India. Illustrate. 6

उत्तर) लिंग गणनापत्र (Gender scorecard) लैंगिक समानता की दृष्टि से प्रभावशाली धारणा है। इस अवधारणा के तहत किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था के प्रदर्शन के मूल्यांकन का एक आधार उसके लिंग संबंधी प्रदर्शन अर्थात - जेंडर स्कोर भी होता है।

भारत के लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभकारी होगा :-

(1) राजनीतिक महिला भागीदारी में वृद्धि। (राजनीतिक दल का जेंडर स्कोरकार्ड पर प्रदर्शन)

(2) आर्थिक संगठन महिला भागीदारी में वृद्धि। (कंपनी का जेंडर स्कोर)

(3) खेल एवं अन्य संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि।

यहाँ क्या लाभ है इसे किस प्रकार लाभ चर्चा करें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner

A3

(कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space))

(इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space))

1.5

जेंडर रूल्स केवल महिला भागीदारी तक ही सीमित नहीं बल्कि महिला संबंधी नीतियों, प्रदर्शन, व्यापक निर्णय क्षमता आदि आयामों पर प्रदर्शन को भी शामिल करता है। निश्चित ही यह, भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है।

(b) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2015 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। 6.5

Critically examine the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016. 6.5

उभयलिंगी व्यक्ति परिभाषित करें

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित होने की प्रक्रिया में है। इसमें उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण में निम्नलिखित प्रावधान हैं। जैसे:-

(1) उभयलिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंगी के रूप में मान्यता देना।

(2) उभयलिंगी संबंधी अधिकारों की प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रावधान।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
Scanned by CamScanner

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(3) विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी लाभ जैसे - आरक्षण आदि का लाभ प्रदान करना।

परंतु, प्रस्तावित विधेयक की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है।

उभयलिंगी व्यक्तियों की परिभाषा एक नकारात्मक रूप में करना (जैसे जो न स्त्री है न ही पुरुष), स्क्रीनिंग अधिकारी द्वारा उभयलिंगी होने का प्रमाण संबंधी प्रावधान एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण की जगह कल्याणकारी दृष्टिकोण की उपस्थिति।

विधेयक प्रमुख ... 3 लाख

1.5

निष्कर्षतः विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में वांछित सुधार किए जा सकते हैं जिससे संबंधित विधि प्रभावकारी होगी।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Scanned by CamScanner